

मंडियों में गेहूं की भरपूर आवक, कीमतें एमएसपी से अधिक

संजीव मुखर्जी

नई दिल्ली, 9 फरवरी

विपणन सत्र 2023-24 के लिए नई गेहूं की फसल मध्य प्रदेश और गुजरात की कुछ मंडियों में आनी शुरू हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अभी फसल अच्छी स्थिति में दिख रही है, लेकिन कीमत 2,500-3,000 रुपये प्रति किवंटल बताई गई है, जो अप्रैल में शुरू होने वाले 2023-24 सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति किवंटल से अधिक है। व्यापार और बाजार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

हालांकि अगले दो महीनों में आवक पूरी तरह से शुरू होने के बाद कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन व्यापारियों ने कहा कि गिरावट सीमित हो सकती है।

क्योंकि आटा मिलों और अन्य के पास भंडार कमजोर था। कुछ व्यापारियों के अनुसार, यह अगले सीजन में अपने अन्न भंडार को फिर से भरने के लिए किसानों से गेहूं खरीदने के केंद्र के लक्ष्य को मुश्किल बना सकता है जब तक कि यह बोनस के साथ एमएसपी से ऊपर न हो।

व्यापारियों ने कहा कि सोमवार को मध्य प्रदेश की देवास मंडी में लगभग 500 बोरी नए गेहूं की आवक हुई और यह 2,950 से 3,100 रुपये प्रति किवंटल पर बिका। जबकि महाराष्ट्र के जालना में लगभग 100 बोरी आई और बिक्री मूल्य 2,800 से 3,000 रुपये प्रति किवंटल था। इसी तरह, राजकोट मंडी में सोमवार को लगभग 1,000 बोरी गेहूं की आवक हुई और 2,800 से



दिल्ली में गेहूं का भाव (रुपये/किवंटल)

केंद्र	1,फरवरी	4,फरवरी	6,फरवरी
दिल्ली	2900/2995	2900/2950	2750

*दिल्ली में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बिकने वाले गेहूं के भाव नोट : एफसीआई ने 2 फरवरी से खुले बाजार में बिक्री शुरू की

स्रोत : आईग्रेन इंडिया

3,000 रुपये प्रति किवंटल भाव पर बिक्री हुई। गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की नई फसल

सबसे पहले आती है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में आती है और अंतिम में उत्तर प्रदेश में जहां गन्ने की फसल की कटाई के बाद

बोआई की जाती है। व्यापारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 15-20 दिनों में आवक बढ़ेगी। इसके बाद कीमतों की स्थिति स्पष्ट होगी।

लेकिन यहां से मौसम कैसा रहेगा, इस पर एक सवालिया निशान बना हुआ है क्योंकि सर्दियों के जाने पर तापमान में किसी भी तरह की असामान्य वृद्धि से गेहूं सिकुड़ सकता है। ऐसा ही 2022-23 में हुआ था, जब अत्यधिक गर्मी के कारण पौधों की वृद्धि के अंतिम चरणों में उत्पादन कम हो गई थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मजबूत मांग के साथ-साथ उत्पादन में गिरावट ने बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए

मजबूर किया।

इस बीच, केंद्र की खुले बाजार में बिक्री योजना शुरू होने के बाद से घरेलू बाजारों में गेहूं की कीमतों में 100-200 रुपये प्रति किवंटल की गिरावट आई है। इसके जरिए इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से करीब 30 लाख टन बेचने की योजना है। एमटी की बिक्री सीधे ई-नीलामी के माध्यम से आटा मिल संचालकों और अन्य के लिए की जाएगी, जबकि बाकी को नामित एजेंसियों के माध्यम से इसे उपभोक्ताओं के लिए आटा में परिवर्तित करने के लिए बेचा जाएगा।

अभी तक दो ई-नीलामी हो चुकी हैं और उनमें करीब 9,20,000 टन गेहूं की बिक्री हो चुकी है।